वर्ष 2015–16 के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- इस वर्ष राज्य में विद्यमान सभी जल स्त्रोतों से 10980.92 लाख रूपये की 11798.72 टन मछली का उत्पादन किया गया।

- विभागीय ट्राऊट फार्मों से इस वर्ष 63.45 लाख रूपये कीमत की 17.626 मीट्रिक टन खाने योग्य ट्राऊट का उत्पादन किया गया है। इन फार्मों से विभाग को कुल 120.969 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस वर्ष निजी क्षेत्र में भी 1398.60 लाख रूपये कीमत की 399.60 मीट्रिक टन ट्राऊट मछली का उत्पादन किया गया है। प्रदेश में रेनबो ट्राऊट के सफलतापूर्वक प्रजनन के परिणामस्वरूप न केवल कुल्लू जिला अपितु शिमला, मण्डी, कांगड़ा, किन्नौर व चम्बा जिलों में भी निजी क्षेत्र में ट्राऊट इकाईयों की स्थापना की गई है।

ट्राउट फार्म बरोट जिला मण्डी

- राज्य में कार्प मछली उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से अमूर कॉमन कार्प तथा हंगेरियन कामन कार्प (चम्पा–I व II) मछली के बीज का आयात किया गया था जिसका इस वर्ष भी सफलतापूर्वक प्रजनन करवा लिया गया है। प्रदेश के निचले क्षेत्रों में कार्प उत्पादन को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा।

जलाशयों में मत्स्य बीज संग्रहण

- इस वर्ष विभाग द्वारा सभी संसाधनों से 465.59 लाख रूपये का राजस्व अर्जित किया गया है जोकि निर्धारित लक्ष्य (154.55) से 311.04 लाख रूपये अधिक है।

- राज्य के प्रमुख जलाशयों में इस वर्ष 5472 (गोविन्दसागर 2550, पौंगडैम 2741, चमेरा 137 व रणजीत सागर 44) माहीगीरों को पूर्णकालीन स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया। इन माहीगीरों द्वारा 12.18करोड़ रूपये मूल्य की 1293.348 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया है, जिससे मछुआरों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है।

- विभागीय कार्प फार्मों से वर्ष 2015–16 में 431.453 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है।

- राज्य में मत्स्य आखेट की गतिविधियों में कार्यरत 12,901 माहीगीरों को निःशुल्क जीवन सुरक्षा निधि के अन्तर्गत लाया गया है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के पंजीकृत मछुआरों/मत्स्य पालकों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर अथवा स्थाई रूप से विकलांग होने की स्थिति में 2.00 लाख रूपये का निशुल्क बीमा कवच, आंशिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में 1.00 लाख रूपये व चिकित्सिा उपचार हेतू 10,000 रूपये का प्रावधान किया गया है।

- इस वर्ष 4641 सक्रिय जलाशय माहीगीरों को बन्द आखेट मत्स्य सीजन के दौरान मु0 55.692 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

- जलाशयों में कार्यरत माहीगीरों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण मत्स्य आखेट उपकरणों को होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु सभी मछुआरों को ''जोखिम निधि योजना'' के अन्तर्गत लाया गया है। इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत 5463 माहीगीरों ने 20/–रूपये की दर से इस कोष में कुल 109,260/–रूपये एकत्रित किए।

- मत्स्य पालन को राज्य में बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 597 नए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।

- मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के अन्तर्गत 10.0353 हैक्टेयर नए क्षेत्रों को मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाया गया है और 11.63 हैक्टेयर पुराने तालाबों का सुधार किया गया।

- पहली बार विभाग के इतिहास में तालाबों में मछली पालन के विकास को लेकर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक घटक (कम्पोनेंट) –नेशनल मिशन थ्रू प्रोटीन सप्लीमेंटस– (NMPS) के अधीन एक्वाकल्चर डिवैलपमेंट फार इंटेग्रेटिड एप्रोच नामक उपयोजना के अन्तर्गत निजि क्षेत्र में 30.00 लाख रू0 की लागत से 3 कार्प हैचरियां स्थापित की जा रही हैं। 1.20 करोड़ रू0 की लागत से 20 हैक्टेयर के नर्सरी तालाब, 4 करोड़ की लागत से 80 हैक्टेयर के मछली पालन तालाबों का निर्माण करवाया जा रहा है जिस पर 40 प्रतिशत अनुदान देय है। 90.00 लाख रू0 की लागत से दो फीड मिल प्लॉंट स्थापित किये जा रहे है तथा 92.00 लाख रू0 की लागत से मछली दोहन के बाद (Post Harvest

प्रधान सचिव मत्स्य हि0प्र0 ऊना में एनएमपीएस के तालाबों का निरिक्षण करते हुए

Infrastructure) मछली को संभालने के लिए 2 बर्फ के कारखाने, 2 मोबाईल मछली विक्रय वाहन, डीप फ्रीजर तथा इंसूलेटिड बाक्स इत्यादि, नव पंजीकृत 2 मत्स्य पालक सहकारी सभाओं के माध्यम से स्थापित किये जा रहे हैं।

- कार्प फार्म नालागढ़ जिला सोलन व देवली (गगरेट) जिला ऊना कार्यशील कर दिये गये हैं तथा इन फार्मों पर वर्ष 2015–16 में मत्स्य प्रजनन व बीज उत्पादन का कार्य आरंभ कर दिया गया है।
- वर्ष 2015–16 में विभागीय वार्षिक योजना बजट 478.28 लाख रूपये था। इसमें से 65.28 लाख अनुसूचित जाति उप योजना के अधीन व मु0 22.09 लाख रूपये जन जातिय उप योजना के अधीन व्यय किये गये। कार्प फार्म कांगड़ा को सजावटी मछली केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा 30.00 लाख रूपये की लागत से दो सजावटी मछली इकाईयां स्थापित की जा रही हैं। कुल लागत में से 12.00 लाख रूपये राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद,15.00 लाख रूपये हि0प्र0 एक्वाकल्चर, फिशिंग एण्ड मारकेटिंग सोसाईटी, बिलासपुर तथा 3.00 लाख रूपये विभागीय बजट से व्यय किये गये।

- 84.60 लाख रूपये की लागत से कार्प फार्म देवली (गगरेट) जिला ऊना व कार्प फार्म सुलतानपुर जिला चम्बा में एक एक आहार संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।
- राज्य के जनजातिय क्षेत्रों में मात्स्यिकी सम्बंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के उद्वेश्य से 4.08 करोड़ रूपये की लागत से थला भरमौर जिला चम्बा में ट्राउट फार्म व 41.11 लाख रूपये की लागत से चूड़ी गांव (धरवाला) में एक्वेरियम हाउस कम म्यूजियम सैंटर चंबा जिला में स्थापित किये जा रहे है। वर्ष 2015–16 में कुल कार्य का लगभग 65 प्रतिशत भाग पूरा कर लिया गया है।
- इस अवधि में विभाग द्वारा 740 मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया, 10 अधिकारियों को पजांब के लुधियाना जिले में नई ब्रीडिंग टैकनोलोजी में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। इसके अतिरिक्त विभाग के 4 अधिकारियों को एक्वाकल्चर इन न्यू एण्ड अन्डर यूटिलाईजड वाटर बौडीज स्कीम के तहत मुम्बई में केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षण सस्थान में प्रशिक्षण दिलवाया गया विभागीय ट्रेनिंग मैनुअल के अनुसार 11 अधिकारियों/कर्मचारियों को विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों व हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला में प्रशिक्षण

दिलवाया गया तथा इसके अतिरिक्त 49 कर्मचारियों को जागरूकता भ्रमण के लिए प्रदेश के भीतर व बाहर भी भेजा गया ।

- राज्य में वर्ष 2015–16 के दौरान 10 चेतना शिविरों का आयोजन करवाया गया जिसके अन्तर्गत 425 अभ्यार्थी लाभान्वित हुए। यह शिविर अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) के अन्तर्गत लगाए जाते हैं तथा एक दिन की अवधि के होते हैं।